

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश



तिब्बत देश

अगस्त, 2026, वर्ष : 47 अंक : 8

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार
पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित
तिब्बत के बारे में सही जानकारी के
साथ हर महीने आपके हाथों में



सिक्क्योंग पेनपा त्सेरिंग सभा को संबोधित करते हुए

प्रधान संपादक
ताशी देकि

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र, डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
मिगमार छमचो

वितरण प्रबंधक

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच - १० लाजपत नगर - ३
नई दिल्ली - ११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचारों से संपादक,
प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया
जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख
अवश्य करें।

समाचार -

Contents

०१. कैरोंग- रसुवा सीमा पर भयानक बाढ़ में हुई जानमाल की हानि पर परम पावन दलाई लामा ने शोक व्यक्त किया 2
०२. सिक्क्योंग पेन्पा शेरिंग ने डॉ. स्वपन दासगुप्ता के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज को संबोधित किया, वरिष्ठ भारतीय हस्तियों से मुलाकात की 2
०३. सिक्क्योंग पेन्पा शेरिंग ने चेक राजदूत डॉ. एलिसका जिगओवा से मुलाकात कर तिब्बतियों के लिए उनके मजबूत समर्थन की सराहना की 2
०४. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का ८०वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 3
०५. सीटीए नेतृत्व ने तिब्बती शहीद लोबगा रंगजेन के सम्मान में धर्मशाला में ४९वें दिन की प्रार्थना सभा और शांतिपूर्ण मार्च की अगुवाई की 4
०६. पावो लोबगा रंगजेन के आत्मदाह के ३३वें दिन ज्यूरिख में १३ तिब्बती संगठनों ने संयुक्त रूप से विशाल मोमबत्ती जुलूस निकाला 5
०७. टोक्यो में तिब्बती और जापानी लोगों ने शहीद लोबगा रंगजेन की याद में 'यूनाइट फॉर तिब्बत' और 'ग्लोबल डे ऑफ एक्शन' मनाया 6
०८. प्रतिनिधि डॉ. शेवांग ग्याल्पो आर्य ने टोक्यो में चीनी समुदाय के बीच 'टोक्यो ह्यूमैनिटीज फोरम' को संबोधित किया 7
०९. चीन की बढ़ती 'एसीमिलेशन पॉलिसी' के विरोध और लोबगा रंगजेन को सम्मान देने के लिए बर्न में २०० से ज्यादा तिब्बती और समर्थक जुटे 8
१०. तिब्बतियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लोबगा रंगजेन की शहादत के ४९वें दिन की प्रार्थना-सभा और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन किया 9
११. पूरे यूरोप में बसे तिब्बती समुदाय ने जिनेवा में लोबगा रंगजेन के आत्मदाह के ४९वें दिन की रस्म अदा की 10
१२. स्विट्जरलैंड में तिब्बतियों ने लोबगा रंगजेन की शहादत के ४९वें दिन जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन किया 11
१३. नॉर्वे के प्रतिष्ठित इरास समारोह में तिब्बती संस्कृति की झलक 12
१४. धर्मशाला में 'लोकतांत्रिक चीन और तिब्बत का भविष्य' पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 12
१५. ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर डीन स्मिथ ने सीमा-पार दमन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के खिलाफ मैग्निट्स्की-शैली के प्रतिबंध लगाने की मांग की 13
१६. तिब्बतियों के लिए चीन का नस्लीय अल्पसंख्यकों से जुड़ा कानून असल में उनका विलोप करने की कोशिश 13
१७. डेगों बांध के विरोध के दौरान चीनी अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के दो साल बाद भी तिब्बती भिक्षु की हालत गंभीर, हिरासत में यातना का व्यापक पैटर्न उजागर 15
१८. आत्मदाह करने वाले तिब्बती कार्यकर्ता की याद में 16

समाचार -

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा

नोरबू ग्राफिक्स, 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार, लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित
जानकारी के लिए भारत -
तिब्बत समन्वय केन्द्र की
वेबसाइट

coordinator@india
tibet.net



प्रो० श्यामनाथ मिश्र

श्री श्याम मंदिर, खेतड़ी
जिला-झुंझुनूं (राजस्थान)
मो.-9079352370

E-mail:- shyamnathji@gmail.com

गत 26 अगस्त, 2026 को तिब्बत एवं उससे सटे नेपाल में आई अचानक बाढ़ से जान-माल की हुई जबरदस्त बर्बादी बारंबार याद आयेगी। ऐसी ही बर्बादी से हमारे भारत में उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बचाव हो गया क्योंकि भावी संकट की सूचना पहले मिलने से समय रहते पूर्व और पूर्ण तैयारी कर ली गई। ऐसी तैयारी में हमारे भारतीय बचाव दल पूर्णतः सफल हैं। इनके द्वारा नेपाल में किये जा रहे सहायता एवं बचाव कार्य की प्रशंसा समस्त विष्व में हो रही है। इस बीच एक प्रश्न उभरा है कि भावी संकट की सूचना चीन सरकार ने तिब्बत एवं नेपाल को क्यों नहीं दी? ऐसी सूचना से तिब्बत और नेपाल को भीषण विनाश से बचने हेतु कम समय में भी उपयुक्त उपाय करने का अवसर मिल जाता। यह दुखद घटना तिब्बत के लांगटांग लिरुंग में बहुत बड़े ग्लेशियर के टूटने और सवा पाँच हजार मीटर नीचे गिरने से हुई। यह सब एकाएक हुआ लेकिन चीन सरकार को अपने वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से इसके प्रामाणिक संकेत पहले से ही मिल रहे होंगे। उसे जानकारी भारत एवं नेपाल समेत उन सभी देशों को देनी थी जो तिब्बत से जुड़े हैं।

टूटा हुआ ग्लेशियर नीचे की झील को तोड़ता हुआ पानी और गाद लेकर भोटेकोषी और त्रिपूल नदियों में पहुँचा। खतरनाक जलस्तर एवं गति एकाएक अधिक बढ़ जाने के कारण नेपाल में महाविनाश देखने को मिला। तिब्बत में चूँकि चीन सरकार ने मीडिया पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं इसलिये वहाँ के प्रामाणिक समाचार मिलना असंभव है। नेपाल में हुई भयंकर तबाही के आधार पर ही तिब्बत में हुए विनाश का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं जबकि यह शोकप्रद विनाशलीला तिब्बत से ही शुरू हुई थी।

तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु परमपान दलाईलामा ने तिब्बत एवं नेपाल में हुई विनाशलीला को दुखद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। स्वतंत्र तिब्बत देश पर सन् 1959 में अवैध नियंत्रण कर उसे चीन का भूभाग बताने वाले उपनिवेशवादी चीन सरकार को चाहिये कि वह संकट की घड़ी में तिब्बत पहुँचकर मदद करने के लिये भारत समेत अन्य देशों को अवसर एवं सहयोग प्रदान करे। उसे इसका भय है कि ऐसा कदम उठाने पर विष्व समुदाय प्रत्यक्ष देख लेगा कि चीन सरकार तिब्बत में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का विनाश कर रही है। विकास के नाम पर वहाँ ग्लेशियर नष्ट हो रहे हैं। भारत-तिब्बत मैत्री संघ की बिहार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य तथा राजनेता एडवोकेट कुमार राज मनोरंजन सिंह ने बताया कि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के लिये चीन सरकार जिम्मेदार है क्योंकि वह तिब्बत में परमाणु कचरा गाड़ रही है। उसे पता है कि एक दिन तिब्बत स्वतंत्र होगा ही इसीलिये वह चीन में विकास के लिए तिब्बत को “परमाणु

डस्टबीन” बना चुकी है। मनोरंजन सिंह ने कहा कि तिब्बती पर्यावरण पर जारी चीनी संकट से छुटकारा दिलाना पूरे विष्व की जिम्मेदारी है।

भारत में कई प्रमुख नदियाँ, जैसे-ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु तिब्बत से आती हैं। म्यांमार में मीकांग यहीं से जाती है। चीन सरकार इन पर बड़े-बड़े बांध बनाकर इनके प्रवाह को नियंत्रित कर रही है। वह स्वेच्छानुसार तिब्बती ग्लेशियर्स से निकली नदियों से प्रभावित देशों में आकस्मिक बाढ़ या सूखा ला सकती है। बड़े बांध बनाने की प्रक्रिया में तिब्बती पर्यावरण तथा प्राकृतिक संपदा के विनाश से भारत सहित तिब्बत के सभी पड़ोसी देश दुष्प्रभावित हो रहे हैं। लांगटांग लिरुंग में विषाल पर्वताकार हिमखंड टूटकर नीचे गिरने, झीलों के अचानक टूट जाने, सप्तकोषी (भोटेकोषी), त्रिपूली एवं अन्य सहायक नदियों में एकाएक कई मीटर तक खतरनाक गति तक जलस्तर बढ़ने से हुए विनाश के बाद चीन की साजिशपूर्ण तिब्बत नीति का विरोध और तीव्र होना चाहिये। वह विपत्तिकाल में भी संपूर्ण विष्व, विषेषकर पड़ोसी देशों को भी, भावी संकट संबंधी आवश्यक सूचनायें नहीं देता।

इसी अगस्त माह (1 से 10 तक) में कैलाश मानसरोवर दर्शन हेतु तिब्बत मुक्ति यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें बि. हार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा झारखंड के 40 तिब्बत समर्थक शामिल थे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बिहार में आरा, मिश्रवलिया-मलउर, पटना, अजग. “बीनाथ (सुलतानगंज), कामराय, जिलेबिया, इनारावरण, राजगीर तथा नालंदा, झारखंड में वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ, दुमका एवं राजरप्पा तथा पश्चिम बंगाल के तारापीठ में तिब्बत मुक्ति यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में जागरुकता के अंतर्गत जगह-जगह विचार गोष्ठी, साहित्य वितरण, भंडारे, शोभायात्रा तथा प्रश्नोत्तर सत्रों का आयोजन किया गया। भारत तिब्बत मैत्री संघ, उत्तर प्रदेश और सुरुचि कला समिति, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा के संयोजक तथा भारत तिब्बत मैत्री संघ, उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉ० अंजनी कुमार मिश्र ने बलपूर्वक कहा कि तिब्बत समस्या का समाधान भारत के हित में है। विचारगोष्ठियों और प्रश्नोत्तर सत्रों में कई स्थानीय लोगों ने दुखपूर्वक कहा कि वे चाहकर भी कैलाश मानसरोवर नहीं जा रहे हैं क्योंकि चीन सरकार ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर इस पवित्र एवं आध्यात्मिक यात्रा को मोटी कमाई का साधन बना लिया है। उनका मत था कि काशी विष्णुनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम की इस यात्रा ने कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा तिब्बत में जारी चीनी दमनकारी नीति संबंधी जागरुकता फैलाने का जो प्रशंसनीय कार्य किया है वह अवश्य अच्छे परिणाम देगा। हर जगह मीडियाकर्मियों ने इस यात्रा में गहरी रुचि लेते हुए इसे व्यापक स्तर पर प्रकाशित-प्रचारित-प्रसारित किया जिससे तिब्बती संघर्ष को नई ऊर्जा मिली है।

◆ ०१. कैरोंग- रसुवा सीमा पर भयानक बाढ़ में हुई जानमाल की हानि पर परम पावन दलाई लामा ने शोक व्यक्त किया

मैं नेपाल के रसुवा क्षेत्र और तिब्बत के कैरांग में आई बाढ़ से हुई जानमाल की हानि की बात सुनकर बहुत दुखी हूँ। मेरी जानकारी में आया है कि इस बाढ़ के कारण के कारण जनहानि के साथ ही बड़ी संख्या में मकान ध्वस्त हो गये हैं। मैं इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और इस हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों समेत तमाम प्रभावित लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मुझे जानकारी मिली है कि इस क्षेत्र में पहले भी आपदाएं आती रही हैं, इससे लगता है कि इस तरह की आपदाएं यहां पर जलवायु परिवर्तन या ऐसे ही किसी अन्य गंभीर कारणों से आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहां तक संभव हो, इनसे बचाव के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि सुनिश्चित हो सके कि ऐसी आपदाएं दोबारा न आएँ।

मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं,

दलाई लामा

२७ अगस्त, २०२६

◆ ०२. सिक्क्योंग पेन्पा शेरींग ने डॉ. स्वपन दासगुप्ता के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज को संबोधित किया, वरिष्ठ भारतीय हस्तियों से मुलाकात की

२४ अगस्त, २०२६

नई दिल्ली, २३ अगस्त। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्क्योंग पेन्पा शेरींग ने नई दिल्ली के 'द लीला पैलेस' में आयोजित एक उच्च-स्तरीय रात्रिभोज (डिनर रिसेप्शन) को संबोधित किया। यह कार्यक्रम डॉ. स्वपन दासगुप्ता के पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के उपलक्ष में आयोजित किया गया था।

सिक्क्योंग पेन्पा शेरींग ने वहां मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. दासगुप्ता को उनकी समर्पित जनसेवा के लिए सराहना की और नई नेतृत्व भूमिका के लिए बधाई दी। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रों में लगातार जुड़ाव, बातचीत और सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।

रात्रिभोज के दौरान सिक्क्योंग ने व्यक्तिगत रूप से डॉ. दासगुप्ता को सफेद स्कार्फ (खटक) और परम पावन १४वें दलाई लामा की तस्वीर भेंट कर बधाई दी। साथ ही उन्होंने भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों और हस्तियों से भी बातचीत की, जिनमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला

सीतारमण और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी शामिल थे। इन मुलाकातों से सद्भावना बढ़ाने और उच्चस्तरीय संबंधों व संपर्क को और मजबूत करने का अवसर मिला।

पद्म भूषण से सम्मानित, पूर्व पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉ. स्वपन दासगुप्ता ने गत १० जून को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। वे अभी भारत की राजधानी में 'बिजनेस टुडे' के 'इंडिया@१०० इकोनॉमी समिट' में वक्ता के तौर पर शामिल होने और पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास व औद्योगिक रोडमैप पर सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेने के लिए आए हुए हैं।

निमंत्रण मिलने पर सिक्क्योंग पेन्पा शेरींग ने इस रात्रिभोज में भाग लिया। उनके साथ नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा के ब्यूरो के प्रतिनिधि जिग्मे शेरींग भी मौजूद रहे।

◆ ०३. सिक्क्योंग पेन्पा शेरींग ने चेक राजदूत डॉ. एलिसका जिगओवा से मुलाकात कर तिब्बतियों के लिए उनके मजबूत समर्थन की सराहना की

२४ अगस्त, २०२६



नई दिल्ली। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्क्योंग पेन्पा शेरींग ने आज २४ अगस्त को चेक गणराज्य के दूतावास में भारत में चेक गणराज्य की राजदूत डॉ. एलिसका जिगओवा से मुलाकात की। यह मुलाकात भारत में राजदूत के तौर पर उनका कार्यकाल पूरा होने के मौके पर हुई।

लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में मुख्य रूप से तिब्बत में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की मौजूदा 'चीनीकरण' की नीतियों पर चर्चा हुई। इसमें 'नस्लीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून' को लागू किए जाने की स्थिति में तिब्बती पहचान पर इसके गंभीर असर पर भी बात हुई। उन्होंने बदलती वैश्विक शक्ति संतुलन, तिब्बती लोगों की मौजूदा स्थिति और 'मध्यम मार्ग नीति' के प्रति सीटीए की अनवरत प्रतिबद्धता पर भी चर्चा की। इस नीति का मकसद बातचीत और तिब्बती लोगों के लिए वास्तविक स्वायत्तता के जरिए तिब्बत के मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजना है। तिब्बती समुदाय के प्रति राजदूत के लंबे

समय से चले आ रहे समर्थन और गर्मजोशी भरे संपर्क के लिए आभार जताते हुए सिक्योंग ने उन्हें पारंपरिक सफेद स्कार्फ (खटक) और 'ग्रीन तारा थंगका' भेंट किया।

राजदूत ने शांति, बातचीत, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल्यों को बनाए रखने की तिब्बती लोगों और सीटीए की लगातार कोशिशों का समर्थन करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सिक्योंग ने राजदूत को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और तिब्बती समुदाय के प्रति उनके लंबे समय से चले आ रहे समर्थन और संपर्क के लिए आभार व्यक्त किया।

इस विदाई समारोह में नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा के कार्यालय (ब्यूरो) के प्रतिनिधि जिग्मे शेरिंग, सचिव ताशी देकि और प्रोटोकॉल अधिकारी तेनजिन पासंग भी शामिल हुए। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और दोनों पक्षों ने उम्मीद जताई कि चेक गणराज्य और तिब्बती लोगों के बीच करीबी रिश्ते और आपसी समझ भविष्य में भी बनी रहेगी।

◆ ०४. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का ८०वां स्वतंत्रता दिवस मनाया

१५ अगस्त २०२६

धर्मशाला। भारत के ८०वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने और भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए १५ अगस्त को गैंगचेन किड्शोंग में संक्षिप्त समारोह का आयोजन किया। समारोह में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तीनों स्तंभों के प्रमुखों, कालोन (मंत्री), निर्वासित तिब्बती संसद (टीपीआईई) के सदस्य, सचिव, सीटीए के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

समारोह की शुरुआत सिक्योंग पेन्पा शेरिंग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई।

इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने तिब्बती लोगों का लंबे समय से समर्थन करने और आतिथ्य के लिए भारत सरकार और यहां के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण समारोह में सीटीए नेतृत्व, गणमान्य व्यक्तियों और कर्मचारियों की भागीदारी और भारतीय राष्ट्रगान का गायन भारत के लोगों के साथ एकजुटता की एक सार्थक अभिव्यक्ति है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर विचार करते हुए सिक्योंग ने कहा कि यह अवसर निर्वासित तिब्बतियों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्य की याद दिलाता है, खासकर तब, जब तिब्बत के अंदर तिब्बतियों को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के शासन के तहत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता पीढ़ियों के संघर्ष और बलिदानों के माध्यम से हासिल की गई, जो तिब्बतियों के लिए प्रेरणा और आशा के स्रोत के रूप में काम करेगी।



सिक्योंग ने तिब्बती स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद किया, जिसमें हाल ही में लोबगा रंगजेन का आत्मदाह भी शामिल है, जिन्होंने तिब्बत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि इस तरह के बलिदानों का तत्काल कोई परिणाम नहीं निकल सकता है, लेकिन तिब्बत के लिए अपनी जान देने वालों का साहस और बलिदान विश्व इतिहास में अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियां इनको याद किया करेगी।

उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि तिब्बती लोग भारत सरकार और लोगों के निरंतर समर्थन के लिए गहरी सराहना व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता के लिए अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेंगे। मीडिया के सवाल के जवाब में, सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने लोबगा रंगजेन की स्मृति में उनके द्वारा आत्मदाह करने के ४९वें दिन २० अगस्त २०२६ को धर्मशाला में एक आधिकारिक प्रार्थना सेवा आयोजित करने के लिए सीटीए और टीपीआईई की सराहना की।

◆ ०५. सीटीए नेतृत्व ने तिब्बती शहीद लोबगा रंगजेन के सम्मान में धर्मशाला में ४९वें दिन की प्रार्थना सभा और शांतिपूर्ण मार्च की अगुवाई की

२० अगस्त, २०२६

धर्मशाला। आज २० अगस्त की सुबह धर्मशाला में एकजुटता और सामूहिक स्मरण कार्यक्रम जैसा माहौल दिखा। तिब्बती समुदाय के सभी वर्गों के लोग त्सुगलाखंग प्रांगण में एक विशेष प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हुए। यह सभा तिब्बती शहीद लोबगा रंगजेन (जिन्होंने आत्मदाह किया था) के निधन के ४९वें दिन आयोजित की गई थी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) की १७वीं कशाग और १८वीं निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह सभा सुबह १०:०० बजे से दोपहर १२:०० बजे तक चली। इसमें तिब्बत मुद्दे के लिए लोबगा रंगजेन की शहादत के प्रति सम्मान प्रकट किया गया और उन तिब्बती देशभक्तों को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने तिब्बत के अंदर और बाहर अपनी जान गंवाई है।

इस कार्यक्रम में भिक्षु, छात्र, स्कूली बच्चे, सीटीए अधिकारी, एनजीओ और स्थानीय तिब्बती बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। इस सुबह के आयोजन ने उन लोगों के साथ एकजुटता का महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जिन्होंने तिब्बत मुद्दे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कार्यक्रम में शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी प्रार्थना और एकजुटता व्यक्त की गई।

प्रार्थना सभा का नेतृत्व नामग्याल मठ के महंथ और भिक्षुओं ने किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में मुख्य न्याय आयुक्त येशी वांग्मो, स्पीकर डोल्मा शेरिंग तेखांग, सिक्योंग पेन्पा शेरिंग, डिप्टी स्पीकर, अन्य न्याय आयुक्त, सीटीए के तीनों स्वायत्त निकायों के प्रमुख, १७वीं कशाग के कालोन और १८वीं तिब्बती निर्वासित संसद के सदस्य शामिल थे।

सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने प्रार्थना सभा से पहले स्थानीय मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि तिब्बती बौद्ध धर्म में किसी व्यक्ति के निधन के ४९वें दिन महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। पिछले सात हफ्तों में दुनिया भर के तिब्बतियों ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरह की गतिविधियों की हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए १७वीं कशाग और १८वीं निर्वासित तिब्बती संसद ने आज की स्मारक प्रार्थना सभा आयोजित की, ताकि लोबगा रंगजेन और उन सभी तिब्बतियों को सम्मान दिया जा सके, जिन्होंने तिब्बत मुद्दे के लिए आत्मदाह किया है। सिक्योंग ने जोर देकर कहा कि इन लोगों का मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना या हिंसा को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि तिब्बत के मुद्दे की ओर ज्यादा ध्यान खींचने की उम्मीद में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम उन लोगों की याद में उनके साथ एकजुटता और समर्थन दिखाने के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने अपनी जान दी।

सिक्योंग ने इस बात पर भी चिंता जताई कि चीनी सरकार 'नस्लीय एकता और प्रगति' के नाम पर ऐसी नीतियां अपना रही है, जिनका मकसद तिब्बती पहचान को कमजोर करना और आखिरकार उसे खत्म करना है। उन्होंने कहा कि चीन 'ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, ग्लोबल सिक्योरिटी

इनिशिएटिव और ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव जैसी पहलों के जरिए दुनिया भर में अपना असर बढ़ाना चाहता है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाले तरीकों के तौर पर पेश करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुनिया भर में चीन का बढ़ता असर और नियंत्रण इसी तरह फैलता रहा, तो आजाद दुनिया धीरे-धीरे उसके असर को स्वीकार करने की आदी हो सकती है, जिससे आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने विश्व समुदाय से आग्रह किया कि वे इस बात को समझें कि ये घटनाक्रम सिर्फ तिब्बत से जुड़े नहीं हैं, बल्कि इनका असर पूर्वी तुर्किस्तान और दक्षिणी मंगोलिया समेत दूसरे इलाकों पर भी पड़ेगा।

प्रार्थना सभा के दौरान सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने लोबगा रंगजेन के जीवन, तिब्बत मुद्दे के लिए उनके जीवन भर के समर्पण और सक्रियता के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने लोबगा का आखिरी संदेश भी पढ़कर सुनाया, जो उन्होंने खुद को आग लगाने से पहले दिया था। इसमें उन्होंने तिब्बतियों से एकजुट रहने और तिब्बत की आजादी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने का आह्वान किया था।

प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने तिब्बती यूथ कांग्रेस द्वारा त्सुगलाखंग के प्रवेश द्वार के सामने एक महीने से ज्यादा समय से आयोजित भूख-हड़ताल को समाप्त कराया और फिर धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड की ओर जा रहे मार्च का नेतृत्व किया।

इस शांति मार्च में तिब्बती नेतृत्व और तिब्बती नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ, भारत-तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री अजीत नेहरिया, धर्मशाला नगर निगम के मेयर श्री शमशेर सिंह नेहरिया और तिब्बत के अन्य मित्र और समर्थक भी शामिल हुए।

हाथों में प्लेकार्ड लिए नारे लगाते और तिब्बत के राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए प्रतिभागियों ने धर्मशाला के मुख्य इलाकों से मार्च किया और फिर धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड पहुंचे, जहां एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, क्रमशः सिक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर द्वारा कशाग और निर्वासित तिब्बती संसद के बयान पढ़कर सुनाए गए।

इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव तेनजिन नोरबू ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार का तिब्बतियों के समर्थन में एक संदेश पढ़कर सुनाया।

कार्यक्रम में तिब्बती यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष ताशी धारग्याल का संबोधन भी शामिल था, जिसके बाद तिब्बत और भारत के राष्ट्रगान गाए गए।

◆ ०६. पावो लोबगा रंगजेन के आत्मदाह के ३३वें दिन ज्यूरिख में १३ तिब्बती संगठनों ने संयुक्त रूप से विशाल मोमबत्ती जुलूस निकाला

०७ अगस्त, २०२६



ज्यूरिख, (स्विट्जरलैंड)। स्विट्जरलैंड में १३ तिब्बती संगठनों ने संयुक्त रूप से ०५ अगस्त २०२६ को ज्यूरिख में एक शांतिपूर्ण मोमबत्ती जुलूस आयोजित किया। यह जुलूस आत्मदाह करने वाले तिब्बती पावो लोबगा रंगजेन के गुजरने के ३३वें दिन उनकी याद में निकाला गया था। इस मार्च में ७०० से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यह मार्च ज्यूरिख के वेर्डमुहलेप्लात्ज से शुरू होकर ज्यूरिख में चीनी दूतावास की ओर बढ़ा।

कार्यक्रम के दौरान, आयोजक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाषण दिए और एक संयुक्त प्रेस बयान पढ़ा। इस बयान में सभा का मकसद बताया गया और लोबगा रंगजेन के आखिरी संदेश को याद किया गया।

तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के यूएन एडवोकेसी अफसर, फुंत्सोक टोंग्याल ने प्रतिनिधि थिनले चुक्की की ओर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने भाषण में उन्होंने लोबगा रंगजेन द्वारा आत्मदाह करने की घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में बात की, जिसमें घटना की जगह, समय, आखिरी संदेश और उनके गुजरने के हालात शामिल थे।

फुंत्सोक टोंग्याल ने बताया कि लोबगा रंगजेन ने चीन की 'नस्लीय एकता' और उससे जुड़ी नीतियों के लागू होने के बाद आत्मदाह किया था। उनके अनुसार, इन नीतियों से तिब्बती संस्कृति, भाषा और पहचान को खतरा था। उन्होंने कहा कि लोबगा रंगजेन के इस कदम का मकसद तिब्बत के हालात की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचना, तिब्बती मुद्दे के लिए ज्यादा अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना और उन नीतियों को रद्द करने की मांग करना था।

लोबगा रंगजेन के आखिरी संदेश के बारे में बात करते हुए फुंत्सोक टोंग्याल ने जोर देकर कहा कि उनकी बातों का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि तिब्बतियों में एकता की कमी है। फुंत्सोक टोंग्याल ने कहा, 'आज, इस विरोध प्रदर्शन के लिए ७०० से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं और १३ अलग-अलग तिब्बती संगठनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह हमारे लोगों की एकता को दिखाता है।'

उन्होंने आगे बताया कि लोबगा रंगजेन ने तिब्बत के अंदर के हालात देखे

थे, भारत में निर्वासित जीवन का अनुभव किया था और तिब्बत व तिब्बती लोगों के लिए परम पावन दलाई लामा द्वारा दशकों से किए जा रहे समर्पित कार्यों को देखा था। अमेरिका जाने के बाद लोबगा रंगजेन ने विदेशों में निर्वासित तिब्बतियों का जीवन भी देखा था। फुंत्सोक टोंग्याल के अनुसार, लोबगा रंगजेन मानते थे कि निर्वासित तिब्बतियों ने आर्थिक स्थिरता हासिल कर ली है और उन्होंने खुद कहा था, 'ऐसा नहीं है कि मेरे पास खाने या रहने की जगह की कमी है। मेरे पास सब कुछ है।' हालांकि, आरामदायक जिंदगी होने के बावजूद उन्हें हर दिन गहरा भावनात्मक दुख होता था, क्योंकि उनकी नजर में, कुछ तिब्बती जो तिब्बत के हालात को अच्छी तरह समझते थे, फिर भी चीनी सरकार के साथ जुड़ गए थे। फुंत्सोक टोंग्याल ने कहा कि इसीलिए लोबगा रंगजेन ने तिब्बतियों से अपनी पहचान याद रखने का आग्रह किया और सभी को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया कि 'मैं तिब्बती हूँ।'

फुंत्सोक टोंग्याल ने यह भी बताया कि लोबगा रंगजेन ने आत्मदाह के लिए चीनी दूतावास के बजाय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को क्यों चुना? उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने आत्मदाह करने वाले लोबगा रंगजेन पहले व्यक्ति नहीं थे। उनके अनुसार १९६५ में वियतनाम युद्ध के विरोध में रोजर एलन लापोर्टे ने वहां आत्मदाह किया था, जिससे लोबगा रंगजेन ऐसा करने वाले दूसरे ज्ञात व्यक्ति बन गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने आत्मदाह की तीन घटनाएं दर्ज की गई हैं। फुंत्सोक टोंग्याल के अनुसार, हालांकि लोबगा रंगजेन आत्मदाह करने वाले पहले तिब्बती नहीं हैं, लेकिन वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने आत्मदाह करने वाले पहले तिब्बती बन गये हैं।

लोबगा रंगजेन के आखिरी पलों को याद करते हुए फुंत्सोक टोंग्याल ने कहा कि बहुत ज्यादा दर्द होने के बावजूद वे शांत रहे और न तो भागे, न चिल्लाए और न ही कूदे। इसके बजाय, वे 'जलते हुए दीपक या मोमबत्ती की तरह' स्थिर खड़े रहे। फुंत्सोक टोंग्याल के अनुसार, शरीर के बुरी तरह जल जाने के बाद लोबगा रंगजेन धीरे-धीरे नीचे झुके, अपने हाथ आगे बढ़ाए और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत की ओर मुंह करके पूरी तरह दंडवत मुद्रा में गिर गए।

फुंत्सोक टोंग्याल ने कहा कि इससे लोबगा रंगजेन का यह विश्वास झलकता है कि उनके आखिरी पलों में भी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय एक मंदिर के समान था- एक ऐसी जगह जहां से उनकी प्रार्थनाएं और संदेश अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच सकते हैं और जहां तिब्बत के मुद्दे के लिए समर्थन मिल सकता है।

फुंत्सोक टोंग्याल ने आगे कहा कि लोबगा रंगजेन का फैसला परम पावन दलाई लामा द्वारा दिए गए अहिंसा के सिद्धांतों के उपदेश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि लोबगा रंगजेन हिंसा का रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और तिब्बतियों तथा व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए अपनी जान दे दी।

अपने भाषण का समापन करते हुए फुंत्सोक टोंग्याल ने चिंता जताई कि

लोबगा रंगजेन के आत्मदाह को एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, फिर भी उनके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने दुनिया भर के तिब्बतियों से अपील की कि वे तिब्बत के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र, सांसदों और सरकारों को अपनी अपील और चिंता भरे संदेश भेजते रहें।

उन्होंने आगे कहा कि भले ही केवल अंतरराष्ट्रीय मान्यता से तिब्बत की आजादी वापस न मिले, लेकिन लोबगा रंगजेन के बलिदान को मान्यता देने से यह सुनिश्चित होगा कि उनके इस काम को अंतरराष्ट्रीय इतिहास में तिब्बत की आजादी के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने किए गए शांतिपूर्ण आत्मदाह के रूप में दर्ज किया जाए। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र के सभी १९३ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को तिब्बत के मुद्दे और पावो लोबगा रंगजेन के संदेश के बारे में जानने और उन्हें बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा।

- तिब्बत कार्यालय, जिनेवा की रिपोर्ट

◆ ०७. टोक्यो में तिब्बती और जापानी लोगों ने शहीद लोबगा रंगजेन की याद में 'यूनाइट फॉर तिब्बत' और 'ग्लोबल डे ऑफ एक्शन' मनाया

०३ अगस्त, २०२६



टोक्यो। जापान में निर्वासित तिब्बती समुदाय और जापानी छात्रों ने ०२ अगस्त को 'स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत जापान' और 'ग्लोबल डे ऑफ एक्शन' अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया और शांति मार्च निकाला। यह आयोजन शहीद लोबसांग पालडेन (लोबगा रंगजेन) की याद में उन्हें सम्मान देने के लिए किया गया था। ज्ञातव्य है कि लोबगा रंगजेन ने एक महीने पहले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने आत्मदाह कर लिया था। इस अवसर पर तिब्बती और जापानी समर्थक हाथों में तिब्बत का राष्ट्रीय झंडा और लोबसांग पालडेन के पोस्टर लेकर जिंगू-दोरी पार्क में इकट्ठा हुए थे।

जापान समेत पूर्वी एशिया के लिए परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय में प्रतिनिधि डॉ. सेवांग ग्याल्पो आर्य ने प्रतिभागियों को 'ग्लोबल

डे ऑफ एक्शन' के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे शहीद लोबसांग पालडेन ने चीन के 'एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ (नस्लीय एकता और प्रगति कानून)' का विरोध करने और इस कानून की आड़ में चीन के खतरनाक इरादों की ओर संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए आत्मदाह किया था। उन्होंने सभी से शहीद लोबसांग पालडेन की बातों को याद रखने और 'नस्लीय कता कानून' के साथ-साथ चीन सरकार द्वारा चीन समेत तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया और अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे अन्याय का विरोध करने का आग्रह किया।

जापान में तिब्बती समुदाय की ओर से दोरजी शिओता और 'स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत जापान' के शेरिंग दोरजी ने प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने सभी तिब्बतियों से एकजुट होने और तिब्बत के मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखकर शहीद लोबसांग पालडेन की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में 'स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत' की तेनजिन चोडोन ने शहीद लोबसांग पालडेन की जीवनी पढ़कर सुनाई।

कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने जिंगू-दोरी पार्क से शांति मार्च निकाला और व्यस्त शिबुया सड़क की परिक्रमा की। उन्होंने तिब्बत की आजादी और न्याय के लिए नारे लगाए और संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) सरकार से दमनकारी कानून को रद्द करने और तिब्बत में तथ्यों की जांच के लिए एक तथ्यान्वेषी दल भेजने का आग्रह किया।

दोपहर में टोक्यो यूनिवर्सिटी के कोमाबा कॉम्प्लेक्स में आत्मदाह और 'नस्लीय एकता कानून' पर एक फिल्म शो और पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें इकेया काओरु की २०१५ की दो घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'लुंगटा' दिखाई गई, जिसमें तिब्बत में रह रहे और निर्वासित जीवन जी रहे तिब्बतियों के संघर्ष और आत्मदाह करने वाले कुछ लोगों की जीवन-कहानी को दिखाया गया। पैनल चर्चा के दौरान फिल्म के निर्देशक इकेया ने तिब्बतियों के साथ काम करने के अपने अनुभव और तिब्बत की करुणापूर्ण संस्कृति के बारे में बात की। उन्होंने अफसोस जताया कि हाल के दिनों में तिब्बत के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के लिए तिब्बतियों को आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

टोक्यो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अको टोमोको ने पैनल चर्चा का संचालन किया और बताया कि कैसे लोबगा रंगजेन ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत के सामने आत्मदाह किया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे तिब्बतियों, उग्रयूरों, दक्षिणी मंगोलियाई लोगों और सीसीपी शासन के तहत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं पर ध्यान दें और उनके समाधान के लिए और अधिक प्रयास करें।

प्रतिनिधि डॉ. सेवांग ग्याल्पो आर्य ने इस फिल्म के निर्देशक इकेया और नाकाहारा को फिल्म के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि इसमें तिब्बती संघर्ष और आत्मदाह के पहलुओं को संक्षेप में और प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी में इस फिल्म और पैनल चर्चा को आयोजित कराने में सहयोग के लिए प्रोफेसर अको के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रतिनिधि आर्य ने संक्षेप में बताया कि तिब्बती लोग आत्मदाह करने के लिए क्यों मजबूर होते हैं और शहीद लोबगा रंगजेन ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत के सामने क्यों आत्मदाह किया। उन्होंने कहा कि तिब्बत में बिगड़ते मानवाधिकार हालात और धार्मिक दमन, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी और चीन के 'नस्लीय एकता और प्रगति कानून' ही मुख्य कारण थे, जिन्होंने लोबगा रंगजेन को सीसीपी शासन के खिलाफ उतरने और संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए आत्मदाह पर मजबूर किया।

'स्टूडेंट्स फॉर तिब्बत जापान' के शेरिंग दोरजी ने चीन के औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों के बारे में बात की और बताया कि कैसे दस लाख से ज्यादा तिब्बती बच्चों को कम्युनिस्ट विचारधारा की शिक्षा देने के लिए इन बोर्डिंग स्कूलों में रखा जाता है और उन्हें अपनी मातृभाषा और धार्मिक संस्कृति की शिक्षा से वंचित रखा जाता है।

यहां पर कार्यक्रम का संचालन 'स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत' की फुजिता योको ने किया। प्रतिभागियों ने पैनल से कई सवाल पूछे, जैसे- जातीय कानून, तिब्बत और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों के हालात, औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल, भारत-चीन संबंध, तिब्बती 'मध्यम मार्ग' दृष्टिकोण का तरीका आदि। फिल्म की स्क्रीनिंग और पैनल चर्चा में लगभग चार घंटे लगे, जो तय समय सीमा से अधिक था। टोक्यो यूनिवर्सिटी में हुए इस कार्यक्रम में लगभग दो सौ लोगों ने भाग लिया।

इस अवसर पर दर्शकों को औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों, परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म के चयन में चीनी हस्तक्षेप और तिब्बती बुलेटिनों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तिकाएं बांटी गईं।

-तिब्बत कार्यालय, जापान की रिपोर्ट

◆ ०८. प्रतिनिधि डॉ. शेवांग ग्याल्पो आर्य ने टोक्यो में चीनी समुदाय के बीच 'टोक्यो ह्यूमैनिटीज फोरम' को संबोधित किया

१७ अगस्त, २०२६



टोक्यो। चीनी एकेडमिक थिंक टैंक 'टोक्यो ह्यूमैनिटीज फोरम (टीएचएफ)' ने 'विश्व शांति के लिए चीन और तिब्बत' विषय पर १६ अगस्त को एक बातचीत और चर्चा का आयोजन किया। इस फोरम को

संबोधित करने के लिए जापान समेत पूर्वी एशिया स्थित परम पावन १४वें दलाई लामा के संपर्क कार्यालय में प्रतिनिधि डॉ. शेवांग ग्याल्पो आर्य को टोक्यो के वासेडा-माची में आमंत्रित किया गया था।

चीनी मूल के निर्वासित मानवाधिकार वकील और फोरम के महासचिव ली जिन्सिंग ने कार्यक्रम में चीनी और जापानी प्रतिभागियों और मीडिया समुदाय के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने दर्शकों से प्रतिनिधि डॉ. आर्य का परिचय कराया और चीन-तिब्बत मुद्दे तथा इसको हल करने की आवश्यकता पर संक्षेप में चर्चा की।

प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने चीनी समुदाय के साथ सीधे रू-ब-रू होने का अवसर प्रदान करने के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन कई संदेहों और गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलेगी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) शासन ने दोनों समुदायों के बीच पैदा की हैं।

प्रतिनिधि ने बताया कि कैसे निर्वासन में रह रहे तिब्बती, चीनी, उग्यूर, दक्षिणी मंगोलियाई और हांगकांग के लोग स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय की चाहत में एकसमान हैं और कैसे उद्देश्य की यह एकता उन्हें अपने देशों में दमन और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट कर सकती है। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोग तियानमेन चौक पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले चीनी छात्रों की मांगों और संघर्ष, नोबेल पुरस्कार विजेता लियू शियाओबो और अन्य लोगों की 'चार्टर ०८' वाली याचिका, हांगकांग के प्रदर्शनकारियों की २०२० की मांगों और चीनियों की २०२२ की 'व्हाइट-पेपर क्रांति' के समय की मांगों के साथ एकजुटता रखते हैं।

उन्होंने विस्तार से बताया कि चीनी और तिब्बती लोगों की मांगें एक ही हैं और ये मांगें चीनी संविधान के दायरे में आती हैं, लेकिन चीनी शासक वर्ग अपने ही देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 'मध्यम मार्ग दृष्टिकोण' के बारे में बात की, जिसका उद्देश्य न केवल चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करना है, बल्कि चीन और तिब्बत को विश्व शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बनाना भी है।

इस चर्चा में ४० से ज्यादा चीनी और जापानी विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने तिब्बत की स्वायत्तता की प्रकृति, परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म और उसके बाद की स्थिति, चीन के नस्लीय एकता और प्रगति कानून समेत आत्मदाह के जरिए विरोध-प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या चीन में लोकतंत्र आने के बाद तिब्बती आजादी की मांग नहीं करेंगे? इस पर प्रतिनिधि आर्य ने जवाब दिया कि खेत मिलने से पहले ही फसल काटने की बात करना जल्दबाजी या बेमानी हो सकती है।

चीनी प्रतिभागियों ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें तिब्बतियों का नजरिया और उनकी आकांक्षाएं ज्यादा स्पष्टता के साथ समझ आईं। उन्होंने कहा कि तिब्बती न तो चीन के विरोधी हैं और न ही चीनी लोगों के विरोधी- जैसा कि सीसीपी शासन द्वारा दिखाया जाता है। उन्होंने आयोजकों से ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया।

प्रतिभागियों को प्रतिनिधि डॉ. आर्य की किताब 'हार्नेसिंग द ड्रेगन्स फ्यूम' का चीनी अनुवाद, 'मध्यम मार्ग दृष्टिकोण' पर किताबें और औपनिवेशिक

बोर्डिंग स्कूलों के संबंधित रिपोर्ट बांटी गई। ताइवान स्थित 'तिब्बत कार्यालय' ने इस कार्यक्रम के लिए परम पावन दलाई लामा की आत्मकथा 'वॉयस फॉर द वॉयसलेस' के चीनी अनुवाद की कुछ प्रतियां उपलब्ध कराईं।

कार्यक्रम में प्रतिनिधि के भाषण का अनुवाद उराशिकी ने किया और तिब्बत हाउस, जापान की चिसा सेल्हा ने कार्यक्रम के समन्वय और दर्शकों के बीच किताबें बांटने में मदद की।

-जापान स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट

◆ ०९. चीन की बढ़ती 'एसीमिलेशन पॉलिसी' के विरोध और लोबगा रंगजेन को सम्मान देने के लिए बर्न में २०० से ज्यादा तिब्बती और समर्थक जुटे

१७ अगस्त, २०२६

बर्न (स्विट्जरलैंड)। बर्न स्थित स्विस संसद के पास शुक्रवार, १४ अगस्त को २०० से ज्यादा तिब्बती और उनके समर्थक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुटे। वे तिब्बती पहचान खत्म करने वाली चीन की 'एसीमिलेशन पॉलिसी' का विरोध कर रहे थे। यह सभा तिब्बती प्रदर्शनकारी लोबगा रंगजेन के आत्मदाह के ४४ दिन पूरे होने के मौके पर भी आयोजित की गई थी। उनकी मौत ने तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान फिर से आकर्षित किया है।

इस प्रदर्शन का आयोजन स्विट्जरलैंड और लिकटेस्टीन में तिब्बती समुदाय, स्विस तिब्बती फ्रेंडशिप एसोसिएशन, स्विस तिब्बती महिला संघ, यूरोपीय तिब्बती युवा संघ और स्विस वी-टैग ने मिलकर किया था।

इसमें तिब्बती समुदाय के नेता, निर्वासित तिब्बती संसद के पूर्व सदस्य, तिब्बत ब्यूरो के पूर्व प्रतिनिधि और जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें परम पावन दलाई लामा की प्रतिनिधि थिनले चुक्की और यूएन एडवोकेसी ऑफिसर फुंत्सॉक टॉपग्याल भी शामिल रहे।

सभा में एकजुटता दर्शाने वाले कई कार्यक्रम हुए, जैसे नारे लगाना, पावो लोबगा रंगजेन की तस्वीर के सामने स्कार्फ भेंट करना, तिब्बती राष्ट्रगान का गायन, तिब्बती शहीदों की याद में एक मिनट का मौन और शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन आदि।

आयोजक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने तिब्बत में मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं पर बात की और लोबगा रंगजेन की शहादत को सम्मान दिया। उन्होंने स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के जवाब में और मजबूत व ठोस कदम उठाएं।

प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने लोबगा रंगजेन को याद करने और तिब्बत में लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता

बढ़ाने के लिए बर्न में जुटे तिब्बती समुदाय और समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया।



उन्होंने कहा, 'आज, लोबगा रंगजेन की आत्मदाह के ४४ दिन पूरे होने पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। इस अवसर पर यहां बर्न में जुटे अपने सभी साथी तिब्बतियों के प्रति मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। वे यहां पर न केवल उनके बलिदान को याद करने के लिए आए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन अत्याचारों की याद दिलाने के लिए भी आए हैं, जिन्हें तिब्बत के अंदर तिब्बती लोग लगातार झेल रहे हैं।' चुक्की ने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए स्विस-तिब्बती फ्रेंडशिप एसोसिएशन, तिब्बती महिला संघ, तिब्बती युवा संघ और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

लोबगा रंगजेन की आत्मदाह का जिक्र करते हुए चुक्की ने कहा कि उनकी कुर्बानी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए ऐसी जबरदस्त अपील होनी चाहिए कि वे तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों की स्थिति पर ज्यादा ध्यान दें। उन्होंने कहा, 'हमने २००९ से तिब्बत के अंदर आत्मदाह के १५७ ज्ञात मामले देखे हैं और आत्मदाह करने वाले हर व्यक्ति ने तिब्बत में आजादी और परम पावन दलाई लामा की वापसी की मांग की है।'

परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से उन्होंने अपनी जान देने वालों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि निर्वासित तिब्बती आजादी पाने के लिए काम करना जारी रखेंगे। चुक्की के भाषण का मुख्य फोकस चीन का 'नस्लीय एकता और प्रगति कानून' था, जिसे १२ मार्च, २०२६ को पारित किया गया और ०१ जुलाई, २०२६ को लागू किया गया है। उन्होंने इस कानून की कड़ी आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह उन नीतियों को और मजबूत करता है, जो तिब्बत की अलग सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा, 'यह कल्पना से भी परे है कि चीनी सरकार इतनी हिम्मत से न केवल तिब्बतियों की बुनियादी आजादी और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करती है, बल्कि कानून के जरिए ऐसे आत्मसात करने को कानूनी मान्यता भी देती है।'

चुक्की ने चेतावनी दी कि ये नीतियां सांस्कृतिक आत्मसात करने से कहीं आगे की चीज हैं और उन्होंने तिब्बत की स्थिति को 'सांस्कृतिक संहार' से गुजरने जैसा बताया। उन्होंने मंदारिन-चीनी भाषा को प्राथमिकता देने, तिब्बती मठों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने और ऐसे उपायों से जुड़े प्रावधानों

पर प्रकाश डाला, जो उनके अनुसार, चीन के बाहर उन लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो तिब्बती मुद्दे का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, 'यह कानून न केवल तिब्बत के अंदर रहने वाले तिब्बतियों को प्रभावित करता है, बल्कि हर उस समर्थक को भी प्रभावित करता है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है और तिब्बत की आजादी के संघर्ष का समर्थन कर रहा है।'

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाएं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार तिब्बतियों के मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा हो। चुक्की ने संयुक्त राष्ट्र से भी आग्रह किया कि वह तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति की जांच के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह चीन और तिब्बत में एक प्रतिनिधिमंडल भेजे, ताकि जमीनी स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण और रिकॉर्डिंग की जा सके।'

उन्होंने स्विट्स सरकार से भी अपील की कि वह चीन पर अंतरराष्ट्रीय कानून और उन संधियों का पालन करने के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ाए, जिनका वह हिस्सा है। तिब्बती समुदाय की ओर से चुक्की ने स्विट्जरलैंड के विदेश विभाग का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने तिब्बत की अपील को स्वीकार किया और तिब्बत की स्थिति को लेकर गंभीरता दिखाई।

उन्होंने तिब्बत मुद्दे पर लगातार समर्थन के लिए स्विट्स संसदीय समूह के सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और स्विट्स सांसदों से आग्रह किया कि वे ऐसे प्रस्तावों पर विचार करें, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति स्विट्जरलैंड के राजनीतिक एजेंडे में मजबूती से बनी रहे।

चुक्की ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि 'आज हम यहां इसलिए जमा हुए हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक तिब्बती ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सीधा सवाल छोड़ा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखें सचमुच कब खुलेंगी और वे इस मामले पर कब ध्यान देंगे? इसके लिए और कितने तिब्बतियों को अपना बलिदान देना होगा?

उनकी बातों ने उन प्रदर्शनकारियों के दिलों को छू लिया, जो तिब्बत के अंदर रहने वाले तिब्बतियों के समर्थन में और तिब्बत की आजादी तथा पहचान बचाने के लिए अपनी जान देने वालों की याद में जमा हुए थे। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय एकजुटता, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और तिब्बती संस्कृति, भाषा व पहचान को बचाने की मांगों को दुहराने के साथ समाप्त हुआ। चुक्की ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात खत्म की कि एक दिन परम पावन दलाई लामा ल्हासा के पोदाला पैलेस लौटेंगे और वहां फिर से प्रवचन करेंगे।

बर्न में हुई यह सभा इस बात की सशक्त याद दिलाती है कि दशकों के दमन के बावजूद, तिब्बती और उनके समर्थक मानवाधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और तिब्बत की विशिष्ट पहचान को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

-तिब्बत कार्यालय, जिनेवा की रिपोर्ट

◆ १०. तिब्बतियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लोबगा रंगजेन की शहादत के ४९वें दिन की प्रार्थना-सभा और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन किया

२१ अगस्त, २०२६



नई दिल्ली। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर २० अगस्त २०२६ को पावो लोबगा रंगजेन उर्फ लोबसांग पाल्डेन की शहादत के ४९वें दिन श्रद्धांजलि सभा और एक शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा के कार्यालय और दिल्ली के तिब्बती समुदाय ने किया। इस सभा में ५०० से ज्यादा तिब्बती, तिब्बत समर्थक और तिब्बत के दोस्त शामिल हुए। यह कार्यक्रम पावो लोबगा रंगजेन द्वारा गत ०२ जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बत मुद्दे के समर्थन में आत्मदाह किए जाने के ४९वें दिन आयोजित होने वाले तिब्बती रीति-रिवाज के तहत किया गया था।

इस विरोध-प्रदर्शन में चीन के तथाकथित 'नस्लीय एकता और प्रगति कानून' पर भी चिंता जताई गई, जो गत ०१ जुलाई से लागू है। इस प्रदर्शन में खासकर, तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति, मानवाधिकार और पहचान पर इसके दुष्प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। सभा में तिब्बत में मानवाधिकारों की लगातार होती खराब स्थिति और तिब्बती लोगों के अधिकारों व सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा पर ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ध्यान देने की मांग की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत पावो लोबगा रंगजेन और तिब्बत मुद्दे के समर्थन में आत्मदाह करने वाले सभी लोगों की याद में सामूहिक प्रार्थना के साथ हुई, जिसके बाद तिब्बत और भारत के राष्ट्रगान गाए गए। उनकी याद में एक मिनट का मौन भी रखा गया।

पावो लोबगा रंगजेन को प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि देते हुए कई तिब्बतियों ने 'आजाद तिब्बत' के नारे लगाए और अपना मुंडन करवाया। यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम इस सभा के खास पलों में से एक था और उनके बलिदान के प्रति एकजुटता को दर्शाता था।

सभा में नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा ब्यूरो के प्रतिनिधि जिग्मे शेरिंग ने शुरुआती भाषण दिया और 'कशाग (तिब्बती सरकार)' का बयान पढ़कर सुनाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोबगा रंगजेन और आत्मदाह करने वाले अन्य तिब्बतियों ने 'चीनी सरकार और

अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान तिब्बती लोगों की दुर्दशा की ओर खींचने के एकमात्र मकसद से अपनी अमूल्य जान कुर्बान कर दी।' उन्होंने तिब्बतियों के समक्ष 'कशाग (तिब्बती सरकार)' की यह अपील भी दोहराई कि वे 'चीनी सरकार की उन नीतियों का विरोध करने में सतर्क, समझदार और एकजुट रहें, जिनका मकसद तिब्बती पहचान को खत्म करना है।'

क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ और न्यू अरुणा नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्षों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के नाम एक अपील पढ़कर सुनाई। इसके बाद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व डिप्टी स्पीकर डोल्मा ग्यारी और पूर्व सांसद श्री अनिल हेगड़े ने सभा को संबोधित किया।

कार्यक्रम का आखिरी संबोधन मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद श्री धर्मेन्द्र यादव ने दिया। उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी तिब्बत के मुद्दे की मुखर समर्थक रही है और इस मुद्दे का समर्थन जारी रखने का भरोसा दिलाया।

क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस की अगुवाई में 'वी शैल ओवरकम (हम होंगे कामयाब)' क्रांतिगीत गाया गया, जो प्रतिभागियों की एकजुटता और आजादी की उम्मीद की सामूहिक भावना को दर्शाता है। कार्यक्रम का समापन साम्यलिंग तिब्बती बस्ती के अधिकारी दोरजी शेरिंग के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान चला और चीन के तथाकथित 'नस्लीय एकता और प्रगति कानून' के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च और विरोध-प्रदर्शन किया गया।

- नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा का ब्यूरो की रिपोर्ट

◆ ११. पूरे यूरोप में बसे तिब्बती समुदाय ने जिनेवा में लोबगा रंगजेन के आत्मदाह के ४९वें दिन की रस्म अदा की

२१ अगस्त, २०२६



जिनेवा (स्विट्जरलैंड)। पूरे यूरोप से १,००० से ज्यादा तिब्बती और उनके समर्थक बुधवार, १९ अगस्त को जिनेवा में इकट्ठा हुए। वे न्यूयॉर्क

में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने लोबगा रंगजेन के आत्मदाह के ४९वें दिन की रस्म अदायगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बती लोगों के अधिकारों, पहचान और आजादी की रक्षा करने की अपील करने के लिए जमा हुए थे।

बड़े पैमाने पर हुए इस प्रदर्शन और प्रार्थना-सभा की शुरुआत पैलेस विल्सन से जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तक मार्च के साथ हुई, जो 'ब्रोकन चेंयर' के पास खत्म हुई। यह 'ब्रोकन चेंयर' बारूदी सुरंगों और हिंसा के विरोध का एक पुराना प्रतीक है। शाम को सभी लोग उसी जगह पर लोबगा रंगजेन और उनके बलिदान की याद में मोमबत्ती जुलूस और प्रार्थना-सभा के लिए इकट्ठा हुए।

इस कार्यक्रम में स्विट्जरलैंड और लिकटेस्टीन, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इटली और इंग्लैंड में निर्वासित जीवन जी रहे तिब्बती समुदाय और संगठन शामिल हुए। इनके साथ स्विस् तिब्बती महिला संघ, गेसेलशाफ्ट श्विजेरिश-तिबेटिश फ्रुडशाफ्ट, यूरोप में तिब्बती युवा संघ और वी-टैग भी मौजूद थे। इस अवसर पर यूरोप भर से आए तिब्बती समुदाय के नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया।

मौजूद खास मेहमानों में जिनेवा की ग्रैंड काउंसिल के सदस्य सेड्रिक जेनरट शामिल थे, जिन्होंने सभा में भाग लिया और उसे संबोधित किया। यूएनपीओ की सचिव मर्स ने भी अपनी बात रखी। गेसेलशाफ्ट श्विजेरिश-तिबेटिश फ्रुडशाफ्ट के अध्यक्ष थॉमस बुचली ने तिब्बत के लिए स्विस् संसदीय समूह का बयान पढ़कर सुनाया। फ्रेंच बोलने वाले स्विस् तिब्बती फ्रेंड्स ग्रुप के प्रतिनिधियों ने भी तिब्बती मुद्दे के समर्थन में बात की।

जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो की ओर से प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने यूएन एडवोकेसी ऑफिसर फुट्सोक टॉपग्याल और ईयू-चीन संपर्क अधिकारी सांग्ये केप के साथ प्रदर्शन में भाग लिया। प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने सभा को संबोधित करते हुए जोर दिया कि यह कार्यक्रम न केवल याद करने का जरिया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने की एक नई अपील भी है। अपने संबोधन में, प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सामने यह जमावड़ा इसलिए भी खास है, क्योंकि आज उस घटना को ४९ दिन पूरे हो रहे हैं, जिसमें लोबगा रंगजेन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने अपनी जान दे दी थी।

उन्होंने कहा, 'आज हम यहां उनके बलिदान को याद करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि हमने अभी भी उम्मीद और भरोसा नहीं खोया है।' उन्होंने याद दिलाया कि १९५९ से ही परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व में निर्वासित तिब्बती लगातार तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के अधिकारों और आजादी के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोबगा रंगजेन का बलिदान उन नीतियों से पैदा हुई गहरी तकलीफ को दिखाता है, जो तिब्बती समुदाय की नजर में तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान, भाषा और विरासत के लिए खतरा है।

प्रतिनिधि चुक्की ने 'नस्लीय एकता और प्रगति कानून' की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इसे लागू करना तिब्बती पहचान और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने चिंता जताई कि यह कानून तिब्बती भाषा और संस्कृति को बचाने और उनके इस्तेमाल पर और रोक

लगा सकता है, साथ ही तिब्बती अधिकारों की वकालत करने वालों पर पाबंदियां भी बढ़ा सकता है।

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि तिब्बती अधिकारों का समर्थन करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को निशाना बनाने वाले प्रावधान सीमा-पार दमन शुरू करा सकते हैं, जिससे प्रतिबंधात्मक नीतियों का असर तिब्बत की सीमाओं से बाहर तक फैल सकता है। उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कहना चाहती हूँ कि हम आज यहां न केवल चीनी कानून का विरोध करने के लिए हैं, बल्कि यह भी कहने के लिए हैं कि अभी भी समय है कि आप तिब्बत और तिब्बत के अंदर रहने वाले तिब्बतियों के साथ खड़े रहें।'

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी निकायों और सरकारों को सीधे संबोधित करते हुए प्रतिनिधि चुक्की ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रियाओं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, राजदूतों और सरकारों से आग्रह किया कि वे केवल चिंता व्यक्त करने से आगे बढ़कर सार्थक कदम उठाएं। उन्होंने कहा, 'अब चुप रहना ठीक नहीं है। यह समय है कि आप आगे आएँ, बोलें और उन बातों पर अमल करें, जिनका आपने वादा किया है।' उन्होंने तिब्बतियों और उनके समर्थकों से उम्मीद न खोने का भी आह्वान किया और एकता तथा निरंतर अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के महत्व पर जोर दिया।

यह कार्यक्रम 'ब्रोकन चेंयर' के पास प्रार्थना और मोमबत्ती जलाने के समारोह के साथ संपन्न हुआ। प्रतिभागियों ने लोबगा रंगजेन की याद में ४९वें दिन की रस्म अदायगी की, साथ ही तिब्बत के लिए शांतिपूर्ण अभियान चलाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उन तिब्बतियों के साथ खड़े होने का आह्वान किया, जो अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म और पहचान पर प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुंडन कराने का एक प्रतीकात्मक समारोह भी आयोजित किया गया, जिसने दिन के कार्यक्रमों में एक गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक पहलू जोड़ा। यह सभा पूरे यूरोप में तिब्बतियों और उनके अंतरराष्ट्रीय समर्थकों के बीच एकजुटता का सशक्त प्रदर्शन थी। प्रतिभागियों ने संयुक्त राष्ट्र के सामने खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र और सरकारों से सार्वभौमिक मानवाधिकारों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की अपनी अपील दोहराई कि तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की आवाज और अधिकारों को न तो नजरअंदाज किया जाए और न ही भुलाया जाए।

जिनेवा से संदेश स्पष्ट था- लोबगा रंगजेन के बलिदान को नहीं भुलाया जाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन नीतियों के सामने चुप नहीं रहना चाहिए, जो तिब्बत की विशिष्ट पहचान, भाषा और सांस्कृतिक विरासत के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती हैं।

-तिब्बत कार्यालय, जिनेवा की रिपोर्ट

◆ १२. स्विट्जरलैंड में तिब्बतियों ने लोबगा रंगजेन की शहादत के ४९वें दिन जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन किया

२५ अगस्त, २०२६

जिनेवा (स्विट्जरलैंड)। स्विट्जरलैंड में तिब्बती लोग २२ अगस्त को जिनेवा के ऐतिहासिक 'पैलेस डेस नेशंस' में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने जमा हुए। वे तिब्बती शहीद लोबगा रंगजेन के आत्मदाह के ४९वें दिन की रस्म अदायगी करने और चीन द्वारा तिब्बत में लगातार किए जा रहे दमन, खासकर 'नस्लीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून' को लागू करने की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रदर्शनकारी पहले 'पैलेस विल्सन' के सामने जमा हुए, जो मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय का मुख्यालय है, और फिर शांतिपूर्वक 'पैलेस डेस नेशंस' की ओर मार्च किया। उन्होंने तख्तियां उठाई और चीन के नए 'एसीमिलेटिव (आत्मसात करने वाले) कानून' की निंदा करते हुए नारे लगाए।

इस विरोध-प्रदर्शन में जिनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय में प्रतिनिधि थिनले चुक्की, रिकोन मठ के महंथ, परम पावन दलाई लामा के पूर्व विशेष दूत केलसांग ग्यालत्सेन, पूर्व प्रतिनिधि केलसांग दोरजी और पूरे स्विट्स परिसंघ से तिब्बती समुदायों के सदस्यों ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर मार्च समाप्त करते हुए प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बतियों को अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में भी नारे लगाने चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के व्यापक समुदाय में जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने तिब्बती शहीद लोबगा रंगजेन के अंतिम संदेशों को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

- जिनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट

◆ १३. नॉर्वे के प्रतिष्ठित इरास समारोह में तिब्बती संस्कृति की झलक

२६ अगस्त, २०२६

ओस्लो। नॉर्वे में निर्वासित तिब्बती समुदाय ने एक बार फिर ओस्लो के सालाना इरास समारोह में हिस्सा लिया। २२-२३ अगस्त को आयोजित इस समारोह में पारंपरिक संगीत और नृत्य के जरिए तिब्बत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया, जिसने समारोह में आए अलग-अलग तरह के दर्शकों का मन मोह लिया। समुदाय ने एक तिब्बती स्टॉल लगाकर तिब्बती कलाकृतियां बेची और तिब्बत के बारे में जानकारी दी। तिब्बती समुदाय ने इसके माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश की।

इरास समारोह संगीत और नृत्य का सालाना उत्सव है, जिसे इरास नेटवर्क के जरिए ओस्लो के निवासी आयोजित करते हैं। इस नेटवर्क में २८ अलग-अलग संस्कृतियों वाले संगठन शामिल हैं। समारोह का मकसद अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए खुशी और गर्व की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही दूसरों की संस्कृतियों की सराहना करना, उनके प्रति समझ और सम्मान को प्रोत्साहित करना है।

यह समारोह ओस्लो के लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं को बेहतरीन बहु-सांस्कृतिक कला प्रदर्शनों का अनुभव करने और उनमें भाग लेने का मौका देता है। यह शहर की विविध कलात्मक अभिव्यक्तियों का जश्न है और एक ऐसी जगह बनाता है, जहां अलग-अलग समुदाय एक-दूसरे के साथ अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को साझा करते हैं।

तिब्बती प्रस्तुतियों की शुरुआत एक युवा तिब्बती ने स्थानीय बोली में की और इसमें युवा और बुजुर्ग दोनों पीढ़ियों के लोगों ने हिस्सा लिया। पारंपरिक तिब्बती पोशाक पहने कलाकारों ने अपनी सुंदर चाल-ढाल, अનોखे नृत्य और सांस्कृतिक नजाकत से दर्शकों का मन मोह लिया।

नॉर्वे के प्रमुख बहु सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने से तिब्बतियों को दुनिया भर की संस्कृतियों (चीन सहित) का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदायों के साथ तिब्बत की अलग सांस्कृतिक पहचान दिखाने का एक अहम मंच मिला।

तिब्बती प्रतिनिधि शेरींग यांगकी ने कहा, 'खासकर ऐसे समय में, जब चीनी कम्युनिस्ट शासन ने गत ०१ जुलाई से लागू तथाकथित 'नस्लीय एकता और प्रगति कानून' के जरिए आत्मसात करने और चीनी संस्कृति में ढालने की नीतियों को संस्थागत रूप दे दिया है और अलग-अलग नस्लों की राष्ट्रीयताओं को एक ही चीनी पहचान में मिलाने की कोशिश जोर-शोर से कर रहा है, नॉर्वे में तिब्बती समुदाय ने एक अहम सांस्कृतिक मंच के जरिए वैश्विक दर्शकों के सामने तिब्बती संस्कृति की समृद्धि और विशिष्टता को बढ़ावा देने का सराहनीय काम किया है।'

तिब्बती समुदाय के लिए यह समारोह अलग-अलग पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का भी एक मौका था। इस समारोह में शामिल हुए ओस्लो के एक तिब्बती निवासी ने कहा, 'नॉर्वे में तिब्बती समुदाय हमारी समृद्ध संस्कृति, संगीत, नृत्य और परंपराओं को बहुत अच्छे से संजोकर रखे हुए है और उन्हें मनाता है। इरास में हमारी

भागीदारी अपनी विरासत को दूसरों के साथ साझा करने और तिब्बत के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार मौका है। इसे और भी खास बात यह बनाती है कि हम पुरानी पीढ़ी को अपनी संस्कृति और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हुए देखते हैं। वे उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अपनी तिब्बती पहचान को अपनाने और अपनी पहचान पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इरास समारोह में तिब्बती समुदाय की भागीदारी यह दिखाती है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम समुदायों के लिए अपनी विरासत को बचाने, नई पीढ़ी को जोड़ने और व्यापक समाज के साथ अपनी अनूठी पहचान साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच कैसे बन सकते हैं। नॉर्वे में रहने वाले तिब्बतियों के लिए, यह समारोह न केवल संगीत और नृत्य का उत्सव था, बल्कि सांस्कृतिक निरंतरता, गर्व और पहचान की एक सार्थक अभिव्यक्ति भी थी।

-लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय की रिपोर्ट

◆ १४. धर्मशाला में 'लोकतांत्रिक चीन और तिब्बत का भविष्य' पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

३१ अगस्त, २०२६



धर्मशाला। धर्मशाला के धौलाधार हाइट्स रिजॉर्ट में ३१ अगस्त २०२६ को 'लोकतांत्रिक चीन और तिब्बत का भविष्य फोरम' नाम का तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ।

फोरम का आयोजन तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट (टीपीआई) के सहयोग से तिब्बती कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड (टीसीडीएफ) द्वारा आयोजित किया गया था। इस फोरम में दुनिया भर से २८ प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें पत्रकार, अनुवादक, विद्वान, नागरिक समाज के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल थे। इनमें से ज्यादातर चीनी मूल के थे। इसका मकसद तिब्बत और चीन से जुड़े मानवाधिकारों और मौजूदा नीतियों पर गंभीरतापूर्वक बातचीत करना था। फोरम का लक्ष्य अहिंसक अभियान और लोकतांत्रिक बदलाव के लिए मजबूत समूह का निर्माण और ठोस रणनीतियां तैयार करना है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा शेरींग ने मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और मुख्य भाषण दिया।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत वाशिंगटन डी.सी. में तिब्बत कार्यालय के चीनी संपर्क अधिकारी सुल्ट्रिम ग्यात्सो के संबोधन से हुई, जिसके बाद तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक और सचिव तेनजिन लेक्ष्य ने स्वागत भाषण दिया। दोनों ने तीन दिवसीय कार्यक्रम और इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।

सभा को संबोधित करते हुए सिक्योंग पेन्पा शेरींग ने कई अहम मुद्दों पर बात की, जिनमें चीन-तिब्बत संबंधों के ऐतिहासिक और मौजूदा पहलू, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का 'मध्यम मार्ग दृष्टिकोण, परम पावन १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म का सवाल, निर्वासित तिब्बतियों और चीनियों के बीच सहयोग का महत्व और चीन-तिब्बत विवाद को सुलझाने में मदद के लिए तथ्यों पर आधारित रचनात्मक बातचीत की जरूरत शामिल थी।

◆ १५. ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर डीन स्मिथ ने सीमा-पार दमन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के खिलाफ मैग्निट्स्की-शैली के प्रतिबंध लगाने की मांग की

२१ अगस्त, २०२६

कैनबरा। 'ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत' सह-अध्यक्ष सीनेटर डीन स्मिथ ने गत २० अगस्त को सीनेट में चीन के नए 'नस्लीय एकता और प्रगति कानून' और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले तिब्बतियों पर इसके असर की आशंका को लेकर चिंता जताई।

सीनेटर स्मिथ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तिब्बती, उग्रूर, हांगकांगवासी समेत अनेक प्रवासी समुदाय रहते हैं, जो आजादी, लोकतंत्र और कानून के शासन की सुरक्षा की तलाश में इस देश में आए हैं। उन्हें कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में इन आजादियों का इस्तेमाल करने से वे या विदेशों में उनके परिवार खतरे में पड़ सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे तिब्बती समुदाय के सदस्यों के लिए निर्वासित तिब्बती सरकार के चुनावों में वोट देना, सार्वजनिक रूप से दलाई लामा का समर्थन करना या अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान जाहिर करना जैसी गतिविधियों को चीनी अधिकारी अपने इस कानून के तहत अनुसार गैरकानूनी मान सकते हैं।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से मांग की कि वह सीमा-पार दमन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा माने और विदेशों में दमन और डराने-धमकाने की कार्रवाई करने या उसका निर्देश देने वाले लोगों के खिलाफ पहले से लागू किए गए प्रतिबंधों (जिनमें मैग्निट्स्की-शैली के प्रतिबंध भी शामिल हों) पर विचार करे।

— तिब्बत कार्यालय, कैनबरा की रिपोर्ट

◆ १६. तिब्बतियों के लिए चीन का नस्लीय अल्पसंख्यकों से जुड़ा कानून असल में उनका विलोप करने की कोशिश

चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने ०१ जुलाई २०२६ को 'नस्लीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून' लागू किया। यह ६५ धाराओं वाला कानून मार्च में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। बीजिंग इसे देश के आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त ५६ नस्लीय समूहों के आत्मसात करने के आधुनिक उपाय के तौर पर पेश करता है। अधिकारी इसे 'चीनी राष्ट्र के लिए समुदाय की मजबूत भावना' कहते हैं। लेकिन तिब्बत में रह रहे लगभग ७० लाख और निर्वासित जीवन जी रहे लगभग १,५०,००० तिब्बतियों के लिए यह कानून कुछ और ही है। यह एक ऐसी परियोजना को कानूनी रूप देने जैसा है, जिसके तहत उन्हें मुख्यधारा में मिलाने की कोशिशें पिछले दो दशकों से चल रही हैं।

- धुंडुप ग्यालपो, २७ अगस्त २०२६

तिब्बत: एक प्रयोगशाला

'नस्लीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून' अचानक नहीं बना। चीन की नस्लीय नीतियों पर नजर रखने वाले शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके मुख्य विचार उन शुरुआती नियमों से आए हैं, जो सबसे पहले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और सिचुआन, युन्नान और किंघाई के तिब्बती आबादी वाले इलाकों में २००९ के आसपास लागू किए गए थे। ये कानून २००८ में तिब्बती पठार पर हुए विद्रोह के बाद लागू किए गए थे। जो चीज एक क्षेत्रीय प्रयोग के तौर पर शुरू हुई थी, वह अब राष्ट्रीय कानून बन गई है।

इस कानून का यह इतिहास बताना इसलिए अहम है, क्योंकि यह चुपचाप अपने पुराने वादे को पलट रहा है। चीन के १९८४ के 'क्षेत्रीय नस्लीय स्वायत्तता कानून' में अल्पसंख्यक इलाकों को 'अपने आंतरिक मामलों का प्रबंधन' करने देने का वादा किया गया था। नया कानून उस पुराने कानून को रद्द नहीं करता, बल्कि उसे बस नाम का बनाए रखता है और उसके ऊपर एक बिल्कुल अलग ढांचा खड़ा करता है। यह एक ऐसा ढांचा है, जो 'एकता' और 'आपसी मिलन' का नाम देकर असल में 'आत्मसातीकरण' को प्रश्रय देता है। अगर कोई कानून खुलेआम तिब्बती स्वायत्तता को खत्म करता, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी निंदा होती। लेकिन ऐसा कानून, जो बस कानूनी तौर पर उसे खत्म कर दे, वही नतीजा बिना ज्यादा विरोध के हासिल कर लेता है।

यह कानून असल में क्या है

इसकी अच्छी-अच्छी बातों के नीचे, कानून की असल धाराएं बहुत सख्त हैं:

भाषा: यह मंदारिन को शिक्षा और सार्वजनिक जीवन की मुख्य भाषा बनाता है। इससे उस व्यवस्था को और मजबूती मिलती है, जिसमें

अनुमानित ८० प्रतिशत तिब्बती बच्चे सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ते हैं। ये स्कूल अक्सर उनके घरों से दूर होते हैं और वहां ज्यादातर पढ़ाई मंदारिन में होती है।

घर का माहौल: इस कानून के अनुच्छेद-२० में माता-पिता से यह अपेक्षा की गई है कि वे बच्चों को 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से प्यार करना' सिखाएं और 'नस्लीय एकता के लिए हानिकारक' किसी भी चीज को प्रतिबंधित मानें। यह नियम सीधे तौर पर परिवारों द्वारा अपने बच्चों से कही जाने वाली बातों पर भी असर डालता है।

जनसांख्यिकीय बदलाव: कानून में 'आपस में जुड़े हुए सामुदायिक माहौल' की बात कही गई है, जो उन पुनर्वास कार्यक्रमों को औपचारिक रूप देती है, जिनसे २००० के बाद से अनुमानित ३३.६ लाख तिब्बती प्रभावित हुए हैं। इनमें गांव बदलने और मजदूरों को दूसरी जगह भेजने की योजनाओं के तहत हटाए गए लाखों लोग शामिल हैं।

असहमति माने अपराध: कानून का अनुच्छेद-६२ उन गतिविधियों को अपराध मानता है, जिन्हें सरकार 'अलगाववादी या चरमपंथी' मानती है। यह तय करने का अधिकार भी सरकार के पास ही है कि कौन सी गतिविधि इस श्रेणी में आती है। यह पैमाना इतना व्यापक है कि इसमें मठों में शिक्षण के तरीके या परिवार द्वारा तिब्बती भाषा बोलने पर जोर देने जैसी बातें भी आ सकती हैं। और

चीन की सीमाओं के बाहर भी असर: कानून का अनुच्छेद-६३ चीन के बाहर रहने वाले उन लोगों और संगठनों पर अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, जो 'नस्लीय एकता को कमजोर करते हैं या अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं'। चीनी अधिकारियों ने खुलकर कहा है कि यह नियम किसी भी देश के आलोचकों पर लागू हो सकता है। यह भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में रहने वाले तिब्बती शरणार्थी समुदायों के लिए सीधी धमकी है।

यह कानून बीजिंग की तिब्बती बौद्ध धर्म पर नियंत्रण पाने की लंबे समय से चल रही कोशिशों को नया कानूनी आधार भी देता है। इसमें पुनर्जन्म लेने वाले लामाओं को मान्यता देने पर सरकार का जोर भी शामिल है। इसी नीति के कारण १९९५ में दलाई लामा द्वारा मान्यता प्राप्त पंचेन लामा (छह साल का बच्चा) गायब हो गए थे और उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया।

आवासीय स्कूल व्यवस्था की बारीकियां: शायद इस कानून का सबसे असरदार तरीका सबसे चुपचाप काम करने वाला है। किसी भी अनुच्छेद में तिब्बती भाषा पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और न ही इसकी जरूरत है। मंदारिन को बढ़ावा देकर और अल्पसंख्यक-भाषा की स्कूली शिक्षा को 'नस्लीय एकता' के अधीन करके, यह कानून उस बोर्डिंग स्कूल व्यवस्था को सुरक्षित करता है, जो पहले से ही ज्यादातर तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों और उनकी भाषा से अलग करती है और यह अलगाव उन सालों में होता है, जो दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो बच्चा साल में नौ महीने मंदारिन वर्चव वाली कक्षाओं में बिताता है और जिसे ज्यादातर हान चीनी शिक्षक पढ़ाते हैं, हो सकता है कि वह आदेश के कारण तिब्बती भाषा भूल जाए। यह नुकसान पीढ़ियों तक चलता रहेगा। यह उस भाषा से जुड़ा है, जिसमें बच्चा सोचता और सपने

देखता है। यह सांस्कृतिक बदलाव का एक धीमा, लेकिन गहरा असर डालने वाला तरीका है, जो किसी भी साफ-साफ पाबंदी से कहीं ज्यादा असरदार होता है।

यहीं पर बीजिंग के 'साझा समृद्धि' के घोषित लक्ष्य में असल टकराव पैदा होता है। ऊंचे इलाकों में रहने वाले उन समुदायों में निवेश करना, जहां सुविधाओं की भारी कमी है, अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह कानून सिर्फ स्कूलों और क्लिनिकों के लिए फंड नहीं देता- बल्कि यह निवेश इस शर्त पर किया जाता है कि लोग सांस्कृतिक और भाषाई रूप से मुख्यधारा में घुल-मिल जाएं। यह विकास और सांस्कृतिक अस्तित्व को एक-दूसरे का पूरक नहीं मानता।

बीजिंग का पक्ष: चीनी अधिकारी उपरोक्त नजरिए को पूरी तरह खारिज करते हैं। वे इस कानून को दमन के बजाय विकास और समानता का जरिया बताते हैं और पश्चिमी सरकारों पर चीन के रिकॉर्ड को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हैं। वे तिब्बत और झिंझियांग में असल बुनियादी ढांचे और नौकरियों में निवेश को पेश करते हैं और बताते हैं कि दूसरे देशों का भी मूल निवासियों के प्रति घुलने-मिलने का अपना इतिहास रहा है। इन तर्कों में दम है। कोई भी सरकार भविष्य में कानून लागू करने के बारे में पूरी पारदर्शिता के साथ कानून नहीं बनाती और विकास के लिए दी गई मदद बुरी नीयत का सबूत नहीं होती।

लेकिन सुरक्षा के नाम पर बनाए गए कानून की असली परीक्षा उस अधिकार से होती है, जो वह कानून लागू करने वालों को देता है और यह अधिकार पहले से चले आ रहे व्यवहार के पैटर्न पर आधारित होता है। यहां, उस पैटर्न में झिंझियांग में बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में रखने की दर्ज घटनाएं, मजबूती से जमा हुआ आवासीय स्कूल प्रणाली, गायब हुए पंचेन लामा और तिब्बती पठार पर दो दशकों से चल रही डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग (जनसांख्यिकीय बदलाव की कोशिशें) शामिल हैं। सरकार के घोषित इरादों से ज्यादा अहम वह बुनियादी ढांचा है, जिसे वह लागू करने के लिए बनाती है और इस पैमाने पर देखें, तो यह कानून उस इतिहास से अलग नहीं है। यह उसे और मजबूत करता है।

वैश्विक प्रतिक्रिया और वैश्विक प्रतिष्ठा दांव पर: इस कानून के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने इस कानून को रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी है कि इससे जबरन आत्मसात करने की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता मिलने का खतरा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के बजाय उनके हितों के खिलाफ काम करता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन इसे जबरन आत्मसात करने की प्रक्रिया को कानूनी रूप देने जैसा मानता है। अप्रैल में यूरोपीय संसद ने भारी बहुमत से इसकी निंदा की थी और अमेरिकी सीनेटर्स के एक द्विदलीय समूह ने इसके देश की सीमाओं से बाहर लागू होने की क्षमता की आलोचना की है।

किसी देश का 'एकता' का दावा वहीं तक जायज है, जहां तक आजादी वह लोगों को असहमति जताने, घर पर दूसरी भाषा बोलने और सुरक्षा तंत्र की इजाजत के बिना पूजा-पाठ करने के लिए देता है। जो कानून 'एकता' के नाम पर परिवार की निजी बातचीत या प्रवासी समुदाय के न्यूजलेटर को अपराध की श्रेणी में डालता है, वह आपसी मेलजोल को

नहीं बचाता, बल्कि नियंत्रण थोपता है।

चीन की योजना इस कानून को धीरे-धीरे लागू करने की है, जिसके लिए पांच साल की योजना बनाई गई है, जो टाउनशिप स्तर तक पहुंचेगा। इससे इसके असर को किसी बड़ी नीति के बजाय अलग-थलग घटनाओं के तौर पर दिखाना आसान हो जाएगा। ठीक इसीलिए सरकारों, पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों की ओर से स्वतंत्र निगरानी अभी शुरू होनी चाहिए, न कि घटना के बाद। तिब्बतियों के लिए, जिन्होंने पहले ही अपनी भाषा को स्कूलों की कक्षाओं से गायब होते और अपने बच्चों को सरकारी आवासीय स्कूलों में जाते देखा है, यह कानून कोई नया खतरा नहीं है। यह एक पुराने खतरे को स्थायी कानूनी मान्यता देने जैसा है।

◆ १७. डेर्गे बांध के विरोध के दौरान चीनी अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के दो साल बाद भी तिब्बती भिक्षु की हालत गंभीर, हिरासत में यातना का व्यापक पैटर्न उजागर

इंटरनेशनल कैपेन फॉर तिब्बत, ४ अगस्त, २०२६

पूर्वी तिब्बत में चीन के विवादित पनबिजली बांध परियोजना का विरोध करने के कारण हिरासत में लिए जाने के दो साल बाद, येना मठ के एक तिब्बती भिक्षु की हालत चेंगदू के एक अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। सूत्रों ने इंटरनेशनल कैपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) को बताया कि हिरासत के दौरान चीनी अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया था।

भिक्षु गोनपो शेरिंग का मामला चीनी हिरासत में तिब्बतियों के साथ होने वाली यातना और दुर्व्यवहार के व्यापक पैटर्न को दर्शाता है। आईसीटी की हालिया 'जस्टिस डिनाइड: द पैटर्न्स ऑफ डेथ्स इन एंड आफ्टर कस्टडी इन तिब्बत (न्याय से इनकार: तिब्बत में हिरासत के दौरान और उसके बाद मौतों का पैटर्न)' शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार, तिब्बत में चीन के हिरासत तंत्र में प्रताड़ना, मेडिकल सुविधा न देना और जवाबदेही का अभाव आम बातें हैं। यहां हिरासत में लिए गए लोगों को तभी रिहा किया जाता है, जब उनकी सेहत इतनी खराब हो जाती है कि वे ठीक नहीं हो सकते।

डेर्गे काउंटी के येना मठ के तिब्बती भिक्षु गोनपो शेरिंग की हालत अभी भी गंभीर है। उन्हें डेर्गे बांध के विरोध प्रदर्शन के दौरान चीनी अधिकारियों ने प्रताड़ित किया था, जिसके दो साल बाद भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

सिचुआन प्रांत के डेर्गे (चीनी: डेगे) काउंटी में येना मठ के प्रशासकों में शामिल ४६ वर्षीय गोनपो शेरिंग को चीनी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने फरवरी २०२४ में चीन द्वारा प्रस्तावित कामटोक (गंगतुओ) पनबिजली बांध के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व करने में मदद की थी। स्थानीय तिब्बतियों और भिक्षुओं ने इस परियोजना का विरोध किया था, क्योंकि इससे येना और वोंटो मठों समेत सदियों पुराने मठों के नष्ट होने और कई गांवों व पवित्र धार्मिक

स्थलों के जलमग्न होने का खतरा था।

आईसीटी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन सरकार ने गंभीर चोटों के बावजूद उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसके बजाय, अधिकारी अस्पताल में उन पर लगातार कड़ी नजर रख रहे हैं। वे लोगों के गोनपो से मिलने-जुलने पर रोक लगा रहे हैं, उनकी देखभाल करने वालों की निगरानी कर रहे हैं और तस्वीरें या वीडियो लेने या शेयर करने पर भी पाबंदी लगाए हुए हैं।

गोनपो शेरिंग की हालत आईसीटी की 'जस्टिस डिनाइड (न्याय से इनकार)' रिपोर्ट की मुख्य बातों को सही साबित करती है। एक तो, तिब्बत में हिरासत ही जानलेवा हो सकता है, उस पर भी हिरासत में तिब्बती लोग हों तो, चीनी अधिकारियों का दुर्व्यवहार सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि हिरासत के बाद भी जारी रहता है। अक्सर हिरासत में लिए गए लोगों के जख्मों के बारे में उनके रिश्तेदारों और परिवारों को जानकारी नहीं दी जाती, कोई स्वतंत्र जांच नहीं होती है। जो लोग जवाब मांगते हैं, उन्हें डराया-धमकाया जाता है और उन पर नजर रखी जाती है। गोनपो का मामला यह भी दिखाता है कि हिरासत में प्रताड़ना और अन्य तरह के दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों को उनके किए अपराधों से छूट मिल जाती है।

इंटरनेशनल कैपेन फॉर तिब्बत की अध्यक्ष तेनचो ग्यात्सो ने कहा, 'गोनपो शेरिंग का मामला कोई अकेली घटना नहीं है। यह तिब्बत में मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, प्रताड़ना, जबरदस्ती गायब करने और बिना सजा के छूट मिलने के एक सुनियोजित प्रणाली का सबूत है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कदम उठाने की जरूरत है।' उन्होंने आगे कहा, 'आईसीटी सरकारों से अपील करती है कि वे सिर्फ चिंता जताने से आगे बढ़ें और चीन पर दबाव डालें कि वह अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के कारण मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी तिब्बतियों को रिहा करे, गायब किए गए लोगों के बारे में जानकारी दे, प्रताड़ना के आरोपों की जांच करे और संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों को तिब्बत में आवागमन को सरल सुलभ बनाएं।

चीनी अदालतों ने २०२४ के मध्य में येना मठ के प्रमुख जामयांग लेक्ष्ये को 'सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने की नीयत से भीड़ इकट्ठा करने' के आरोप में या'आन जेल में चार साल की सजा सुनाई।

(आईसीटी सूत्र)

दमन और जबरन पुनर्शिक्षण जारी

चीनी अधिकारियों ने फरवरी २०२४ में बांध निर्माण के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शनों पर व्यापक कार्रवाई करते हुए गोनपो शेरिंग सहित १०० से अधिक तिब्बतियों को गिरफ्तार कर लिया था।

चीनी अदालतों ने २०२४ के मध्य में येना मठ के प्रमुख जामयांग लेक्ष्ये को 'सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की नीयत से भीड़ इकट्ठा करने' के आरोप में याआन जेल में चार साल की कैद की सजा सुनाई। गोनपो शेरिंग को इसी तरह के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई गई थी, हालांकि पुलिस दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के दौरान लगी गंभीर चोटों के

कारण उन्हें आपातकालीन चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

इधर, सूत्रों ने आईसीटी को बताया कि रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि कामटोक बांध पर निर्माण और जबरन स्थानांतरण रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों को चीनी अधिकारी तेजी से डरा रहे हैं और स्थानीय मठवासी समुदायों पर राजनीतिक मांगें थोप रहे हैं।

येना और वोटो दोनों मठों में भिक्षुओं को नियमित रूप से सरकारी निर्माण परियोजनाओं को बाधित न करने और आधिकारिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए लिखित प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये अभियान चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बती बौद्ध संस्थानों पर राजनीतिक नियंत्रण कड़ा करने और पर्यावरण, धार्मिक और सांस्कृतिक चिंता की शांतिपूर्ण अभिव्यक्तियों को दबाने के व्यापक प्रयास को दर्शाते हैं।

प्रस्तावित कामटोक बांध चीनी सरकार द्वारा द्रिचु (यांगत्जी) नदी के ऊपरी हिस्से समेत १३ जलविद्युत बांध बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इनमें से नौ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और सिचुआन प्रांत की सीमा पर हैं। डेर्ज और जोमडा काउंटियों की सीमा वाली परियोजना का नेतृत्व मुख्य रूप से चीन हुआडियन कॉर्प द्वारा सरकार समर्थित कई संस्थाओं के एक संघ के माध्यम से किया जाता है, जिसमें चाइना हुआडियन ग्रुप कंपनी लिमिटेड (४८ प्रतिशत), तिब्बत डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनी लिमिटेड (२० प्रतिशत), सिचुआन टिएटू कांगबा इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (२० प्रतिशत), और हुआडियन इंटरनेशनल पावर कंपनी लिमिटेड (१२ प्रतिशत) शामिल हैं।

तिब्बतियों के लिए इन परियोजनाओं का विरोध करना इसलिए लाजिमी हो जाता है कि ये परियोजनाएं तिब्बतियों के विस्थापन और गहन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले पवित्र स्थलों पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। गोनपो शेरिंग जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिरासत और यातना चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में विकास परियोजनाओं के विरोध को दबाने के लिए अपनाए जाने वाले गंभीर उपायों को उजागर करती है और आईसीटी की 'जस्टिस डिनायड' रिपोर्ट में दर्ज मानवाधिकार उल्लंघन के व्यापक तंत्र के बारे में चिंताओं को मजबूत करती है।

वर्तमान स्थिति: शहीद

नाम: धामचोए

पेशा : पूर्व में बौद्ध भिक्षु

प्रदर्शन की तारीख: २७ अगस्त, २०१२

स्थान: कीर्ति मठ, तिब्बत

उम्र: १७ वर्ष

वर्तमान स्थिति: शहीद

REMEMBERING TIBETAN SELF-IMMOLATORS

Tibet Memory Series, BHR
Central Tibetan Administration
27 August 2012




LOBSANG KELSANG

Occupation - Monk
Date of Protest - 27th August 2012
Location - Kirti Monastery, Tibet
Age - 18
Status - Deceased

DHAMCHOE

Occupation - Former Monk
Date of Protest - 27th August 2012
Location - Kirti Monastery, Tibet
Age - 17
Status - Deceased

Igniting their bodies on fire, Tibetan youths Lobsang Kelsang and Dhamchoe shouted slogans condemning China's repressive policies and ongoing oppression in Tibet. Both of them succumbed to their fatal injuries in the hospital that very evening. These tragic self-immolations stem directly from the PRC government's deliberate erasure of Tibetan grievances, driving brutal human rights violations that systematically destroy Tibet's distinct identity and way of life. Their sacrifices mirror their families' immense grief: Lobsang was a relative of Phuntsok, a monk who self-immolated last March, while Dhamchoe was the brother of Tenzin Choedon, a teenage nun who sacrificed herself in February.

◆ १८. आत्मदाह करने वाले तिब्बती कार्यकर्ता की याद में

नाम: लोबसांग केलसंग

पेशा: बौद्ध भिक्षु

प्रदर्शन की तारीख: २७ अगस्त, २०१२

स्थान: कीर्ति मठ, तिब्बत

उम्र: १८ वर्ष

अपने शरीर को आग के हवाले करते समय दोनों तिब्बती युवाओं-लोबसांग केलसंग और धामचोए ने तिब्बत में चल रही चीनी दमनात्मक कार्रवाइयों और चीन की बर्बर नीतियों के विरोध में नारे लगाए। दोनों को गंभीर रूप से जली अवस्था में सुबह-सुबह अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों का यह दर्दनाक बलिदान पीआरसी द्वारा तिब्बत की समस्याओं को ठीक से न सुलझाने और मानवाधिकारों के बर्बर दमन के कारण तिब्बत की विशिष्ट पहचान और जीवन-शैली को सुनियोजित तरीके से संहार करने के खिलाफ चेतावनी देने वाला है। दोनों का बलिदान उनकी पारिवारिक परंपरा की कड़ी में ही है। लोबसांग केलसंग पिछले मार्च में आत्मदाह करने वाले भिक्षु फुंत्सोक के संबंधी थे, जबकि धामचोए गत फरवरी में आत्मदाह करने वाली किशोर वय की भिक्षुणी तेनजिंग चोएडेन के भाई थे।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.

Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.

You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.

We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Coordinator

India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले मैं, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूँ कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदार भागीदारी रहा है।

तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और कूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।

आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नहीं रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से खाना हो चुका है।

इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे हैं। और आप सभी से यह निवेदन करता हूँ कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे हैं तो उसकी पुष्टी हमें तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीचे लिखे गये पता या ई-मेल पर भेज सकते हैं।

अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमें समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि

कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पता: भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच-10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर-03, नई दिल्ली-110024

फोन: 011-29830578

ई-मेल: coordinator@indiatibet.net



कशाग और निर्वासित तिब्बती संसद शहीद लोबसांग पालदेन के सर्वोच्च बलिदान के 49वें दिन संयुक्त रूप से प्रार्थना सभा आयोजित करेंगे।

REMEMBERING TIBETAN SELF-IMMOLATORS



Tibet Advocacy Section, DHR
Central Tibetan Administration
27 August 2026



LOBSANG KELSANG

Occupation - Monk

Date of Protest - 27th August 2012

Location - Kirti Monastery, Tibet

Age - 18

Status - Deceased

DHAMCHOE

Occupation - Former Monk

Date of Protest - 27th August 2012

Location - Kirti Monastery, Tibet

Age - 17

Status - Deceased

आत्मदाह करने वाले तिब्बती कार्यकर्ता की याद में